नौ हजार करोड़ रुपये से बसेगी शिवालिक टाउनशिप

- एमडीए ने तैयार की कार्ययोजना, दिल्ली रोड पर बसेगी टाउनशिप
- पहले फेस की जमीन खरीदने को वीसी ने लगाई अफसरों की टीम

जासं, मुरादाबादः मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत जमीन खरीदने को मदद मिलने से पीतलनगरी के विकास को पंख लगने जा रहे हैं। दिल्ली रोड पर ग्यारह गांवों की जमीन पर बसने वाली शिवालिक टाउनशिप पर कुल नौ हजार करोड़ रुपये खर्च होने हैं। इसमें आधी धनराशि सरकार से बिना ब्याज पर एमडीए को 20 साल के लिए मिलनी है। शेष रुपये एमडीए को ही लगाने हैं। टाउनशिप के पहले फेस की जमीन खरीदने के लिए अधिकारियों की टीम को लगा दिया गया है।

एमडीए बोर्ड ने सितंबर 2023 में 1250 हेक्टेयर जमीन पर शिवालिक टाउनशिप बसाने को स्वीकृति दी थी। नया मुरादाबाद से तीन गुणा बड़े क्षेत्रफल में बसने वाली इस योजना में हर वर्ग के लिए रहने को घर मिलेगा। टाउनशिप के लिए पहले चरण में 320 हेक्टेयर जमीन खरीदी जानी है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत शासन ने पहले फेस की जमीन खरीदने के लिए 200 करोड़ रुपये दे दिए हैं। इस धनराशि से जमीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। टाउनशिप में पहले चरण में रसूलपुर सुनवाती, डिडौरा और डिडौरी गांव के किसानों की जमीन खरीदी जानी है। एमडीए उपाध्यक्ष शैलेष कुमार ने जमीन खरीदने के लिए टीम बना दी है। छह हेक्टेयर जमीन खरीद भी जा चुकी है। वीसी का कहना है कि 50 हेक्टेयर जमीन की सहमति मिल चुकी है। किसानों की सुविधा के लिए एमडीए कार्यालय में ही सभी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। शिवालिक टाउनशिप के लिए सोनकपुर, शाहपुर तिगरी, भीमाठेर, रसूलपुर सुनवाती, डिडौरा, डिडौरी, लोदीपुर, चौधरपुर, खदाना, सलेमपुर गांव के किसानों की जमीन खरीदी जानी है। उन्होंने बताया कि शिवालिक टाउनशिप पर कुल नौ हजार करोड़ रुपये खर्च होने हैं। इसमें से जमीन खरीदने के लिए करीब चार हजार करोड़ रुपये शासन देने को तैयार है। पांच हजार करोड़ की व्यवस्था एमडीए को करनी है। गोविंदपुरम और सह्याद्री (सोनकपुर योजना) को लांच धन की व्यवस्था करेंगे। शिवालिक टाउनशिप के पहले चरण के लिए कुल 686 करोड़ की स्वीकृति दी है। जमीन खरीदने के साथ धनराशि शासन से मिलती रहेगी।

इस तरह बसेगी शिवालिक टाउनशिपः शिवालिक टाउनशिप आवासीय फ्लैट के अलावा आइटी सिटी, एजुकेशन सिटी, मेडिसिटी, स्पोर्ट्स स्टेडियम, मेगा फूड, पार्क के अलावा रामगंगा नदी पर दो ब्रिज बनाए जाएंगे। इस टाउशिप में एक परिवार की जरूरत के हिसाब से हर वस्तुएं उपलब्ध होगी। बाजार के लिए कहीं भी जाना नहीं होगा। इस योजना के माध्यम से करीब 49 हजार लोगों को मकान और अन्य संपत्तियां मिलेंगी।